23 per cent or 24 per cent. We hope to raise it to 26 per cent or 27 per cent. This can only be done if you have attractive savings instruments. We have short-term savings instruments like *Vikas Patras* and Savings Certificates. Long-term savings instruments are insurance and pension funds. When I announced the Jeevan Suraksha in the Budget, it was aimed at savings. That is another long term saving instrument by which a person saves Rs. 250 a month and gets about Rs. 3,500 a months at the end of the term or so. Therefore, insurance all over the world and in India would promote savings. The higher the savings, the more the resources available for investment. Since these savings are long term savings, they would go into long term investment. That is the answer to Mr. Singla's question. Thank you, Sir.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We have Special Mentions. I would take the sense of the House. It is already 5.35 P.M.

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): We will take up Special Mentions today itself, instead of tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN: It is your suggestion. What about other Members? ...*(Interruptions)* ... Okay.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Mr. Vice-Chairman, Cabinet Ministers have to go to attend a Cabinet meeting.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): प्रायोरिटी पर रखे जाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ऐसी प्रायोरिटी तो होती नहीं हैं। क्वेश्चन आवर पहले होगा, फिर जीरो आवर होगा, फिर दूसरा लेजिस्लेटिव बिजिनेस होगा .... **(व्यवधान)**

अभी कैबिनेट मीटिंग भी शिड्यूल्ड है। कैबिनेट मंत्री जाएंगें। दूसरे मंत्री रहेंगे। फिर यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मंत्री जी नहीं है।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): My colleague, the Minister of State would be here.

THE VICE -CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): It is okay.

Problems of farmers of Bihar due to water logging and submergence of large tracts of land

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही आवश्यक विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। बिहार के लाखों किसान इस विषय से जुड़े हुए हैं ।

लक्खीसराय, पटना, शेखपुरा और नालंदा इन चार जिलों में एक भूखंड है जो करीब ढाई लाख एकड़ का है। वह कटोरे के तल्ले की तरह, सासर के निचले हिस्से की तरह जमीन है। हमेशा आधी दर्जन से ज्यादा नदियों का पानी खासकर गंगा का पानी बारिश के समय उसमें जमा हो जाता है। इस पानी का जमाव अक्टूबर महीने तक रह जाता है। नतीजा यह है कि इस जमीन में न तो धान की फसल हो सकती है और देर से पानी की निकासी होती है इसलिए न ही रबी की फसल सही तरह से हो पाती है। जब कभी पानी की निकासी पहले हो जाए तो यहां बहुत बड़े पैमाने पर दलहन की उपज होती है। अगर इस इलाके में सही मायने में पानी की निकासी की व्यवस्था हो और रबी की फसल के समय सिंचाई की व्यवस्था हो तो पूरे हिंदुस्तान को यह दाल खिला सकता है। यह ताल इलाका कहा जाता है। यह जो कटोर के तल्ले की तरह जमीन होती है इसको बिहारी भाषा में ताल कहा जाता है। तो यह मोकामा बहिया? ताल अकेले पूरे हिंदुस्तान को दाल खिला सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पर तरह तरह की योजनाएं बनीं - पहले मुख्य मंत्री हुए थे डा. श्रीकृष्ण सिंह, उनके समय में ताल विकास योजना बनीं - लेकिन कागज पर रह गयी। थोड़ा बहुत काम जहां तहां हुआ लेकिन वह भी समय के साथ बेकार हो गया। बारम्बार इसके बारे में बातें होती आयी लेकिन कोई निश्चित बात कभी नहीं हो पायी, न ही कोई निश्चित आधार इसका कभी बना। पिछले दिनों जब श्री के.एल. राव साहब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनवायी थी। उस कमेटी के तहत इंक्वायरी की गयी और उस इंक्वायरी में कुछ सुझाव भी दिए गए थे। मैं विस्तार से उन बातों पर नहीं जाना चाहती हूं यहां क्योंकि सदन का बहुत समय लगेगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि श्री के.एल. राव साहब ने जो कमेटी बहाल की थी उस कमेटी के जो